

मुख्यमंत्री भजनलाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा परिवारी से सीधे रूबरू हुए

उन्होंने सचिवालय में राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन का निरीक्षण किया व समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए

जयपुर, 9 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान और प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को जयपुर के शासन सचिवालय स्थित 'राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181' का निरीक्षण

- मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रात्रि में प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों को आपात स्थिति मानते हुए संबंधित अधिकारी से समन्वय कर तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को जयपुर के शासन सचिवालय स्थित "राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181" का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं परिवारियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गंगापुरसिटी के विकास कुमार से फोन पर उनके क्षेत्र में क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की समस्या को संवेदनशीलता के साथ सुना एवं परिवारी को समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन देते हुए, अधिकारियों को तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए, जिसकी अनुपालना में स्थानीय प्रशासन

द्वारा कुछ घंटे में ही क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को दुरुस्त कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान, मुख्यमंत्री वीडियो कॉल के जरिये भी झालावाड़ के परिवारी अनीश एवं सर्वाईमाधोपुर के परिवारी रिकू कुमार से सीधे रूबरू हुए। इस दौरान परिवेदना से संबंधित विभाग के अधिकारी भी वीडियो कॉल पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने परिवारी की समस्या को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही

उसके निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नेक्स्ट जनरेशन राजस्थान संपर्क की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया। उन्होंने शिकायतों की विश्लेषण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली एवं 'आर्टिफिशल इंटेलिजेंस आधारित 'संपर्क जीपीटी' के कार्यों और विश्लेषण क्षमता का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रात्रि में प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों को आपात स्थिति मानते हुए, संबंधित

अधिकारी से समन्वय कर, तत्काल समाधान के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान क्वालिटी परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, हेल्पलाइन सेंटर की कार्यप्रणाली, शिकायत पंजीकरण, फॉलो-अप एवं मॉनिटरिंग व्यवस्था की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हेल्पलाइन के कर्मिकों से समय-समय पर फीडबैक लिया जाए एवं अच्छा काम करने वाले कर्मिकों को प्रोत्साहित भी किया जाए।

दिल्ली में छात्रों के पीजी की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज होगी

नई दिल्ली, 09 अक्टूबर। दिल्ली में पेइंग गेस्ट (पीजी) आवासों में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने पहल तेज कर दी है। राजधानी में छात्रों के पीजी आवासों से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इसके माध्यम से यह जानकारी मिल सकेगी कि छात्र किन जगहों पर रह रहे हैं और वहां उन्हें कौन-कौन सी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा, दिल्ली में चिह्नित 100 पीजी आवासों का अगले तीन दिनों में निरीक्षण करने की योजना है। इसका उद्देश्य आवासों की स्थिति और सुरक्षा

- तीन दिन में 100 चिह्नित पीजी आवासों की स्थिति व सुरक्षा मानकों की जांच की जायेगी

मानकों की जांच करना है। दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना के बाद छात्र आवासों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। इसी पृष्ठभूमि में सरकार पीजी व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। योजना के तहत, भवनों में सुरक्षा मानकों और

संबंधित नियमों के पालन की स्थिति की जांच की जाएगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और संयुक्त टीमें अगले तीन दिनों में चिह्नित 100 पीजी आवासों का निरीक्षण करेंगी। इस पहल का मकसद संभावित सुरक्षा खामियों की पहचान करना और छात्रों के लिए सुरक्षित आवास व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद की अध्यक्षता में छात्र आवास एवं सुरक्षा से जुड़ी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने का फैसला लिया गया।

बाबूलाल कटारा को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
प्राथी के एकमार्च बेटे का विवाह 12 दिसंबर को होना तय हुआ है। उसकी पत्नी मानसिक रूप से गंभीर बीमार है। ऐसे में उसे विवाह की व्यवस्थाएं और रीति-रिवाजों में शामिल होने के लिए साठ दिन की अंतरिम जमानत का लाभ दिया जाए। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी ने आरपीएससी का सदस्य होते हुए वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के सामान्य ज्ञान व शैक्षिक मनोविज्ञान विषय का पेपर लीक कर लाखों रुपए वसूल हैं। अभी चुनाव का समय है और आरोपी मतदाताओं को भी प्रभावित कर सकता है। इसके

अलावा, उसका बेटा एमबीबीएस कर रहा है और उसने अपनी सगाई समारोह की स्वयं व्यवस्था की है। ऐसे में वह शादी की व्यवस्था भी कर सकता है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज करते हुए उसे 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक पुलिस अधिश्ठा में विवाह समारोह में शामिल होने की अनुमति दी है। दूसरी ओर एडीजे कोर्ट ने एसआई भर्ती, स्कूल व्याख्याता और कृषि व्याख्याता भर्ती परीक्षा से जुड़े तीन मामलों में आरोपी को साठ दिन की अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।

भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
करियर इस बात को दर्शाता है कि दुनिया पर में कानून के शासन को समर्थन देना, मजबूत करना और उसका विस्तार करना कितना जरूरी है। न्याय और मानव गरिमा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन लोगों को प्रेरित करती है, जो ज्यादा शांतिपूर्ण दुनिया बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने उल्लेखनीय करियर के दौरान, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय, "इन्टरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर रवांडा" तथा "इन्टरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट" में काम किया है। इसके अलावा, वे

संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त भी रह चुकी हैं। उन्होंने कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर संयुक्त राष्ट्र के जांच आयोग का नेतृत्व भी किया। पिछले के सबसे उल्लेखनीय कार्यों में उनके वे महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं, जिनसे यह स्थापित हुआ कि बलात्कार और यौन हिंसा को नरसंहार तथा मानवता के विरुद्ध अपराध माना जा सकता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने शुक्रवार को अपनी पूर्व जज को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने का स्वागत किया। न्यायालय ने कहा कि यह

भाजपा के आठ और सपा के दो राज्यसभा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित

लखनऊ, 09 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी के आठ और समाजवादी पार्टी के दो राज्यसभा सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। नामांकन पत्रों की जांच एवं नाम वापसी की समय सीमा पूर्ण होने के बाद केवल 10 उम्मीदवार ही बचे थे, इसलिए मतदान कराने की जरूरत नहीं पड़ी।

शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी को प्रमाणपत्र सौंपा गया।

वहीं, भारतीय जनता पार्टी के धर्मपाल सिंह, विद्याशंकर सोनकर, प्रियंका रावत, गोपी पांडे, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, राम प्रताप सिंह और श्रुति गंगवार को प्रमाणपत्र सौंपा गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव 2026 में निर्विरोध निर्वाचित होने पर भाजपा के सभी प्रत्याशियों को बधाई दी है।

राहुल गांधी के नेतृत्व में 10 नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की

मुलाकात से पहले संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक विपक्ष के 150 सांसदों ने पैदल मार्च किया

नई दिल्ली, 09 अक्टूबर। शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसदों के एक ग्रुप ने संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च किया। जहां 10 नेताओं ने राष्ट्रपति भवन पहुंच कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।

राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा, पूरा देश जानता है कि वोट चोरी हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी इसके सूत्रधार हैं, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार इसे लागू करने वाले हैं। भारत के राष्ट्रपति ने आज इस बात से इनकार नहीं किया।

10 नेताओं को ही ग्रुप मीटिंग के लिए अंदर जाने दिया गया और बाकी प्रदर्शनों ने सरकार की नींव हिला दी है। मार्च से पहले पत्रकारों से बात करते हुए, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, मांग वही है जो पूरे देश की है: बेईमानी के पूरे ढांचे को खत्म करना और ज्ञानेश कुमार एक

- राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश जानता है कि वोट चोरी हो रही है। नरेन्द्र मोदी इसके सूत्रधार हैं तथा अमित शाह व ज्ञानेश कुमार इसे लागू करने वाले हैं।

ब्लॉक के लगभग 150 सांसदों की बैठक के बाद यह मार्च निकाला गया। 16 अलग-अलग पार्टियों के 16 नेताओं ने राष्ट्रपति को सौंपे जाने वाले ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत के चुनाव आयोग (ईसी) के कामकाज पर चिंता जताई गई।

इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में विपक्ष के प्रदर्शनों ने सरकार की नींव हिला दी है। मार्च से पहले पत्रकारों से बात करते हुए, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, मांग वही है जो पूरे देश की है: बेईमानी के पूरे ढांचे को खत्म करना और ज्ञानेश कुमार एक

ढाल की तरह खड़े हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोरोई ने कहा, सभी देशभक्त देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में लगे हैं, चाहे वे किसी राजनीतिक दल के सदस्य हों या न हों। मैं उन सभी देशभक्तों को सलाम करता हूं, जो सड़कों पर उतरे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के आव्हान के मद्देनजर मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और ट्रेन सेवाओं को रद करने का जिक्र करते हुए सरकार पर डर के कारण ऐसा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति डरता है, वह आज नहीं तो कल मरेगा ही।

केरल हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री विजयन, पत्नी व दामाद के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए

ईडी की कोचीन मिनरल्स से जुड़े रिश्वत के मामले की जाँच रिपोर्ट पर हाई कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया

कोच्चि, 09 अक्टूबर। केरल हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) से जुड़े कथित रिश्वत मामले का है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच की थी और ईडी की रिपोर्ट के आधार पर अब केरल हाई कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति ए. बदरहीन ने अधिवक्ता के. एम. शाहजहां की याचिका खारिज कर ली। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि पुलिस को प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों पर प्रारंभिक जांच करने के बजाय प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए। ईडी ने दलील दी थी कि उसकी रिपोर्ट को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट माना जा सकता है और इसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। हालांकि, राज्य सरकार ने इस दलील का

- प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि सीएमआरएल ने "सूचना प्रौद्योगिकी परामर्श सेवा" की आड़ में पुत्री वीणा की अब बंद हो चुकी कंपनी "एक्सालॉजिक सोल्यूशंस" को फर्जीवाड़ा कर के 2.78 करोड़ रुपए का भुगतान किया था।

विरोध करते हुए कहा था कि एजेंसी की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं है और इसके लिए प्रारंभिक जांच जरूरी है।

केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार ने हाल में ईडी के उस पत्र के आधार पर पुलिस जांच का आदेश दिया था, जिसमें राज्य पुलिस प्रमुख से विजयन, वीणा और रियास के खिलाफ जांच कराने को कहा गया था।

एजेंसी ने आरोप लगाया है कि सीएमआरएल ने "सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) परामर्श सेवाओं" की आड़ में वीणा की अब बंद हो चुकी कंपनी 'एक्सालॉजिक सोल्यूशंस' को

फर्जीवाड़ा करके 2.78 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।

हरमाड़ा की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
पुलिस ने मृतक के परिजनों से संपर्क कर घटना की सूचना दे दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए कांठिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

पुलिस घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच कर रही है। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है।

पंजाब सीएम के ओएसडी की सुनवाई नहीं करेंगे जस्टिस नागू

नई दिल्ली, 09 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय के जज, जस्टिस शील नागू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुमन के खिलाफ सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली

याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। जस्टिस नागू पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रहने के दौरान कई उन मामलों पर सुनवाई कर चुके हैं जो आम आदमी पीढ़ से जुड़ी थीं।